भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1543 का उत्तर

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान

1543. श्रीमती भारती पारधी:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु चिहिन्त/शुरू की गई रेललाइन परियोजनाओं का राज्य-वार विशेष रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर आदि वस्तुओं के परिवहन के लिए चिहिन्त मार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के तीव्र विकास हेतु कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में दिनांक 04.12.2024. को लोक सभा में श्रीमती भारती पारधी और श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे के अतारांकित प्रश्न सं. 1543 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है न कि राज्य-वार किया जाता है, चूँकि रेल परियोजनाएं विभिन्न राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफारवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता हैं।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अक्टूबर, 2021 में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) के शुभारंभ से अवसंरचनात्मक परिवहन परियोजनाओं की योजना और निष्पादन में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण आया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित पूरे देश में फैले नेशनल मास्टर प्लान ने संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विभागों के बीच सहयोग के माध्यम से रेलवे, जहाजरानी, सड़क मार्ग, दूरसंचार, पाइपलाइन आदि जैसे अवसंरचनात्मक क्षेत्रों के बीच सहक्रियता स्थापित की है, जिससे तेज गति से योजना बनाने के साथ ही परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक मंजूरी में तेजी आई है।

भारतीय रेल ने अपनी परियोजना नियोजन प्रक्रिया में गति शक्ति के सिद्धांतों को आत्मसात किया है और अब सभी नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं का सर्वेक्षण पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) के तहत विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना के विकास के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य एकीकृत नियोजन, संभार तंत्र की दक्षता में वृद्धि और लोगों, माल/वस्तुओं जैसे कृषि उत्पादों, उर्वरकों, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर आदि की निर्बाध आवाजाही के लिए अंतराल को दूर करना और

रणनीतिक महत्व के स्थानों, सीमावर्ती क्षेत्रों, औद्योगिक समूहों, पत्तनों, खदानों, बिजली संयंत्रों, गांवों आदि से सम्पर्क सहित सेवाएं प्रदान करना है।

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित भारतीय रेलवे में लगभग 566 रेल परियोजनाओं को गति शक्ति जीआईएस प्लेटफॉर्म पर मैप किया गया है और इस प्लेटफॉर्म पर और अधिक परियोजनाओं को मैप/योजनाबद्ध किया जा रहा है। पीएम गति शक्ति संस्थागत तंत्र का उपयोग जमीनी सर्वेक्षण, भूमि रिकॉर्ड, मार्ग के संरेखण के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और इससे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की गुणवत्ता में वृद्धि हुई और परियोजना लागत में कमी आई है।

रेलवे परियोजनाओं के शीघ्र अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में शामिल हैं (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं को प्राथमिकता देना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर निधियों के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि (iv) क्षेत्र स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की बारीकी से निगरानी, और (vi) भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीवन संबंधी मंजूरी में तेजी लाने और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप 2014 से कमीशनिंग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

व्यापक योजना और विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय के परिणामस्वरूप, नई पटरियां बिछाने/कमीशनिंग करने की गति में भी निम्नानुसार वृद्धि हुई है:-

अवधि	कमीशन की गई नई पटरियां	कमीशन की गई नई पटरियों का वार्षिक औसत
2009-14	7,599 कि.मी.	4.2 कि.मी. प्रतिदिन
2014-24	31,180 कि.मी.	8.54 कि.मी. प्रतिदिन (2 गुना से अधिक)

गत दो वर्षों अर्थात 2022-23 और 2023-24 के दौरान भारतीय रेल पर यात्री और मालभाड़ों यातायात के लिए 10,552 कि.मी. नए रेल पथ चालू किए गए हैं।

*****